भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं. 395
गुरुवार, दिनांक 03 फरवरी, 2022 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>सौर ऊर्जा का उपयोग</u>

395. श्री प्रताप सम्हा:
डॉ. उमेश जी. जाधव:
श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:
श्री रमेश बिधूड़ी:
श्री बी. वाई. राघवेंद्र: क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) क्या देश में सौर ऊर्जा के उपयोग में वृद्ध हुई है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक के जिलों सहित राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) देश में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने और इसके उपयोग को प्रोत्साहित करने के लए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं वद्युत मंत्री
(श्री आर. के. संह)

(क) जी, हाँ।

(ख) देश में स्थापत सौर क्षमता मार्च, 2014 की 2632 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2021 तक 48088 अनुलग्नक-I में दी गई है।

कर्नाटक में स्थापत सौर क्षमता भी मार्च, 2014 की 31 मेगावाट से बढ़कर दिनांक 31.12.2021 तक 7497 7497 मेगावाट हो गई है। कर्नाटक में जिले-वार स्थापत सौर क्षमता अनुलग्नक-II में दी गई है।

(ग) और (घ): सरकार ने सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लए कई कदम उठाए हैं। ब्यौरा अनुलग्नक-III में दिया गया है।

अनुलग्नक-I

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारां कत प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लि खत अनुलग्नक-I

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति अनुसार देश में स्था पत राज्य-वार संचयी सौर क्षमता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	क्षमता (मेगावाट)*
1	अंडमान और निकोबार	29.22
2	आंध्र प्रदेश	4292.37
3	अरुणाचल प्रदेश	5.61
4	असम	59.15
5	बिहार	169.48
6	चंडीगढ़	52.64
7	छत्तीसगढ	308.83
8	दादरा और नगर हवेली	5.46
9	दमन और दीव	40.72
10	दिल्ली	209.66
11	गोवा	18.37
12	गुजरात	6206.34
13	हरियाणा	593.20
14	हिमाचल प्रदेश	45.04
15	जम्मू और कश्मीर	24.49
16	झारखंड	53.56
17	कर्नाटक	7496.80
18	केरल	306.30
19	लद्दाख	7.80
20	लक्षद्वीप	0.75
21	मध्य प्रदेश	2592.15
22	महाराष्ट्र	2506.81
23	म णपुर	6.36
24	मेघालय	0.19
25	मजोरम	1.53
26	नागालैंड	1.00
27	ओ डशा	405.22
28	पुडुचेरी	11.87
29	पंजाब	1051.09
30	राजस्थान	9979.72
31	सक्किम	2.76
32	त मलनाडु	4757.76
33	तेलंगाना	4154.42
34	त्रिपुरा	9.41
35	उत्तर प्रदेश	1990.28
36	उत्तराखंड	540.49
37	पश्चिम बंगाल	151.00
कुल		48087.85

*इसमें रूफटॉप सौर क्षमता शा मल है।

अनुलग्नक-II

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकत प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक-II

दिनांक 31.12.2021 की स्थिति के अनुसार कर्नाटक में स्थापत जिले-वार संचयी सौर क्षमता

क्र.सं.	जिला	क्षमता (मेगावाट में)*
1	बागलकोट	166.00
2	बंगलोर ग्रामीण	35.00
3	बेलगावी	330.40
4	बेल्लारी	474.50
5	बंगलुरु शहरी	1.00
6	बीदर	415.00
7	चामराजनगर	227.00
8	चक्कबल्लपुर	92.00
9	चक्कमंगलुरु	0.00
10	चत्रदुर्ग	680.00
11	दक्षण कन्नड़	0.00
12	दावनगेरे	106.80
13	धारवाड़ा	50.00
14	गदग	228.00
15	हसन	31.50
16	हावेरी	93.00
17	कलबुर्गी	321.00
18	कोडागू	0.00
19	कोलार	121.00
20	कोप्पल	294.60
21	मंड्या	59.00
22	मैसूर	65.50
23	रायचुर	282.38
24	रामनगर	97.50
25	शवमोगा	1.00
26	तुमकुर	2588.38
27	उडुपी	0.00
28	उत्तर कन्नड़	0.00
29	वजयपुरा	260.80
30	यादगरी	142.50
	कुल	7163.86

* इसमें सौर रूफटॉप क्षमता शामल नहीं है।

अनुलग्नक-II

'सौर ऊर्जा का उपयोग' के संबंध में पूछे गए दिनांक 03.02.2022 के लोक सभा अतारांकत प्रश्न सं. 395 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखत अनुलग्नक-II

देश में सौर ऊर्जा सहित अक्षय ऊर्जा को बढावा देने के लए सरकार द्वारा कए गए वभन्न उपाय

- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष वदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना,
- 30 जून, 2025 तक चालू होने वाली परियोजनाओं के लए सौर और पवन वद्युत की अंतर-राज्य बिक्री के लए अंतर-राज्य पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों को माफ करना,
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा करना,
- लगाओ और चलाओ (प्लग एंड प्ले) आधार पर अक्षय ऊर्जा डेवलपरों को भूम और पारेषण उपलब्ध कराने के लए अल्ट्रा मेगा अक्षय ऊर्जा पार्कों की स्थापना करना,
- प्रधानमंत्री कसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभयान (पीएम-कुसुम), सौर रूफटॉप चरण-II, 12,000 मेगावाट सीपीएसयू योजना चरण-II आदि जैसी योजनाएं,
- हरित ऊर्जा कॉरिडोर योजना के तहत अक्षय वद्युत की निकासी हेतु नई पारेषण लाइनें बिछाना और नई सब-स्टेशन क्षमता वकसत करना,
- सौर फोटोवोल्टेक प्रणाली/उपकरणों की स्थापना के लए मानकों को अधसूचत करना,
- निवेशों को आकर्षत करने और सुवधाजनक बनाने के लए परियोजना वकास एकक की स्थापना करना, करना,
- ग्रड संबद्ध सौर पीवी परियोजनाओं और पवन वद्युत परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लए टैरिफ आधारित स्पर्धात्मक बोली के लए मानक बोली दिशानिर्देश,
- सरकार ने यह आदेश जारी कए हैं क वद्युत की आपूर्ति साख पत्र (लेटर ऑफ क्रेडट - एलसी) या अग्रम भुगतान के माध्यम से की जाएगी ताक वतरण लाइसेंसधारियों द्वारा अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित हो सके।

*****